दीवानी पुनरीक्षण

न्यायमूर्ति प्रीतम सिंह पत्तर के समक्ष

श्रीमती सूरज कौर –(प्रतिवादी) – याचिकाकर्ता

बनाम

सोम दत्ता – (वादी) – उत्तरदाता

दीवानी पुनरीक्षण 1974 की संख्या 1429

17 अक्तूबर 1975

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1)—धारा 20—सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)—धारा 104(1), आदेश 23 नियम 3 और आदेश 43, नियम 1(एम)—वसीयत की वैधता या असलियत —क्या वह धारा 20 के तहत मध्यस्थता या रेफरी को भेज सकते है - मध्यस्थता का संदर्भ और रेफरी का संदर्भ - के बीच अंतर – अभिनिर्धारित किया गया - रेफरी का संदर्भ अमान्य ठहराया गया - ऐसा आदेश - चाहे अपील योग्य हो।

अभिनिर्धारित गया कि वसीयत की वैधता या वास्तविकता या अन्यथा का प्रश्न साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 20 के तहत मध्यस्थता या रेफरी के पास नहीं भेजा जा सकता है और इसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वसीयत की प्रोबेट से संबंधित कानून के अनुसार तय किया जाना चाहिए। किसी मुकदमे में विवादित मामलों पर निर्णय लेने के लिए किसी तीसरे पक्ष का संदर्भ और लागत का प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के अर्थ के अंतर्गत विवादग्रस्त मामले के संदर्भ में जानकारी के लिए उस पक्ष का संदर्भ नहीं है, बल्कि मध्यस्थता के लिए एक संदर्भ है। उस अधिनियम की धारा 20 में 'सूचना' शब्द का अर्थ तथ्य के प्रश्न पर एक बयान है, न कि किसी प्रकार का निर्णय। यदि पार्टियां रेफरी के बयान का पालन करने के लिए सहमत होती हैं तो रेफरी केवल तथ्य के प्रश्न पर अपने ज्ञान या विश्वास के अनुसार बयान देता है और इस बयान को पार्टी या पार्टियों की स्वीकृति माना जाता है; जिसने साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के तहत संदर्भ दिया और न्यायालय मामले का फैसला करता है और ऐसे बयान के आधार पर निर्णय सुनाता है और उस पर डिक्री पारित करता है। एक रेफरी पूछताछ करने और साक्ष्य लेने और फिर ऐसे साक्ष्य के आधार पर निर्णय सुनाने का हकदार नहीं है। हालाँकि, मध्यस्थता का सार यह है कि मध्यस्थ मामले का फैसला करता है और पक्ष आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं और उसके फैसले की वैधता को चुनौती दे सकते हैं, और अगर फैसला बरकरार रखा जाता है, तो यह एक फैसले की प्रकृति में होता है जिसे बाद में एक कोर्ट की डिक्री में शामिल किया जाता है। मध्यस्थ या तो अपने ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ सकता है या पूछताछ कर सकता है और साक्ष्य रिकॉर्ड कर सकता है और फिर ऐसे साक्ष्य पर अपना निर्णय दे सकता है।

(पैरा १४ और १५)

अभिनिर्धारित किया गया कि जहां ट्रायल कोर्ट का मानना है कि मामले को निर्णय के लिए रेफरी के पास नहीं भेजा जा सकता है और संदर्भ अमान्य है और परिणामस्वरूप रेफरी का निर्णय अवैध और शून्य है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट ने पार्टियों के बीच हुए समझौते को रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया है और परिणामस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 43 के नियम 1 का खंड (एम) लागू नहीं होता है। इसलिए, संदर्भ को अमान्य ठहराने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती।

(पैरा ७)

1919 के अधिनियम IX की धारा 44 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत याचिका, श्री के.एल. वासन, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव के अंबाला कैंप, दिनांक 9 अक्टूबर, 1974 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए, श्री हरि राम, वरिष्ठ उप- न्यायाधीश, गुड़गांव के दिनांक 28 नवंबर, 1973

के आदेश को उलटने के लिए, और मामले को कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए निचली अदालत में भेज दिया और पक्षों को 22 अक्टूबर, 1974 को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया, और हर्ज़े के बारे में कोई आदेश नहीं दिया।

जी सी मित्तल, याचिकाकर्ता की और से अधिवक्ता
एस पी जैन उत्तरदाता की तरफ़ से अधिवक्ता

निर्णय

1) यह गुड़गांव में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला के 9 अक्टूबर, 1974 के आदेश के खिलाफ प्रतिवादी सूरज कौर द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका है, जिसके तहत उन्होंने सोम दत्त वादी की अपील को स्वीकार कर लिया और वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, गुड़गांव के 28 नवंबर, 1973 के आदेश को रद्द कर दिया, और कानून के अनुसार मामले में आगे की कार्यवाही के लिए मामले को उनके पास भेज दिया।

2) इस मामले के तथ्य यह हैं कि बहादुर सिंह, निवासी गांव बलूदा, तहसील और जिला गुड़गांव, गांव बलूदा और भोंडसी, तहसील और जिला गुड़गांव में स्थित भूमि का मालिक था, जिसका विवरण वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'ए' में दिया गया है। प्रतिवादी सूरज कौर, बहादुर सिंह की पत्नी है। 15 अप्रैल, 1970 को बहादुर सिंह की मृत्यु हो गई, और उनके पास कोई पुरुष संतान नहीं थी। बहादुर सिंह ने वादी के पक्ष में 15 मार्च, 1969 को एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की थी, जिसमें मुकदमे में जमीन और अन्य संपत्तियां भी उसे दी गईं थीं। हालाँकि, प्रतिवादी सूरज कौर ने कथित तौर पर एक वसीयत बनाई थी जिसे बहादुर सिंह ने उसके पक्ष में निष्पादित किया था और संपत्ति की विरासत के हकदार होने का दावा कर रही थी। सोम दत्त वादी ने इस आशय की घोषणा के लिए यह मुकदमा दायर किया कि वह इस मुकदमे में इस भूमि का मालिक है और सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, गुड़गांव के न्यायालय से राशि लेने का हकदार है, क्योंकि वह बहादुर सिंह का, इन संपत्तियों का एकमात्र उत्तराधिकारी है और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित वसीयत जाली है और उसका संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है। विकल्प में प्रार्थना की गई कि यदि वाद में भूमि पर उसका कब्जा नहीं पाया गया तो उसके पक्ष में कब्जे की डिक्री पारित की जाये।

3) प्रतिवादी ने यह मुकदमा लड़ा। वादी में लगाए गए आरोपों से इनकार किया गया। वादी के पक्ष में मृतक द्वारा निष्पादित कथित वसीयत के तथ्य और वैधता से इनकार किया गया था। यह दलील दी गई थी कि वादी के पक्ष में कथित वसीयत, यदि कोई हो, रद्द कर दी गई थी और बहादुर सिंह ने 28 दिसंबर, 1969 को अपनी आखिरी वसीयत उसके पक्ष में निष्पादित की थी और वह विवाद में संपत्ति की हकदार है। पार्टियों की इन दलीलों पर निम्नलिखित मुद्दे ट्रायल कोर्ट द्वारा 25 अप्रैल, 1972 को तय किए गए थे: -

(1) क्या बहादुर सिंह ने 15 मार्च 1969 को वादी के पक्ष में कोई वैध वसीयत निष्पादित की थी?

(2) यदि प्रकरण क्रमांक 1 सिद्ध हो जाता है तो क्या बहादुर सिंह ने 28 दिसम्बर 1969 को प्रतिवादी के पक्ष में कोई आगामी वैध अपंजीकृत वसीयत की थी? यदि हाँ, तो किस प्रभाव से.

(3) क्या मुकदमा चलने योग्य नहीं है जैसा कि लिखित बयान में बताया गया है?

(4) क्या वादी के पास आरोप के अनुसार कार्रवाई का कोई कारण नहीं है?

(5) क्या मुकदमा कार्रवाई के कारणों की गलत व्याख्या के लिए बुरा है?

(6) राहत.

4) इसके बाद, वादी का साक्ष्य दर्ज किया गया और उसने 12 फरवरी, 1973 को अपना सकारात्मक साक्ष्य बंद कर दिया और मामले को प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए 21 मार्च, 1973 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उसी तारीख को यानी 12 फरवरी, 1973 को, पार्टियों ने एक संयुक्त आवेदन दिया जिसमें कहा गया कि इस मामले के फैसले के लिए उन्होंने गंगा राम सरपंच, लख्मी चंद, टेक चंद, शेर सिंह, मंगतू, रंजीत और माम चंद को रेफरी के रूप में नियुक्त किया है और वे साक्ष्य दर्ज करने और पूछताछ करने के हकदार होंगे। पार्टियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति और रेफरी द्वारा दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। आगे यह उल्लेख किया गया था कि यदि रेफरी में से कोई भी मर जाता है या इस तरह कार्य करने से इनकार करता है, तो शेष छह रेफरी मामले का फैसला करेंगे और गंगा राम सरपंच के पास निर्णायक वोट होगा। हालाँकि, यदि दो रेफरी इस तरह कार्य करने से इनकार करते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो शेष रेफरी बहुमत मत से निर्णय देंगे। सोम दत्त वादी का बयान भी उसी तारीख यानी 12 फरवरी, 1973 को न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि यह आवेदन प्रदर्शनी पी.एक्स. उसे पढ़ा गया था और उसने इसे सही माना और वह रेफरी के संदर्भ से सहमत था और उनके द्वारा दिए गए निर्णय से बाध्य होगा और वह उस निर्णय के खिलाफ कोई अपील या पुनरीक्षण दायर नहीं करेगा। इसी प्रकार, प्रतिवादी श्रीमती सूरज कौर का बयान भी वरिष्ठ उप न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया। वरिष्ठ उप-न्यायाधीश ने 12 फरवरी, 1973 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"पार्टियों द्वारा दिए गए बयानों के मद्देनजर, आवेदन प्रदर्शनी पी.एक्स में उल्लिखित व्यक्तियों को संबंधित पार्टियों के दावों के संबंध में 26 फरवरी, 1973 तक अपना निर्णय देने के लिए रेफरी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस आदेश की सूचना रेफरी को तुरंत भेजी जाए।"

5) शेर सिंह और मंगतू रेफरी ने इस तरह की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। शेष पांच रेफरियों ने 2 मार्च, 1973 को अपना निर्णय न्यायालय में दाखिल किया, जिसमें केवल यह उल्लेख किया गया था कि सोम दत्त वादी के मुकदमे को सूरज कौर प्रतिवादी के खिलाफ डिक्री किया जाए और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाए। इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादी सूरज कौर ने 28 मार्च, 1973 को आपत्तियाँ दायर कीं, जिसमें आरोप लगाया गया कि पार्टियों का इरादा मध्यस्थों को नियुक्त करना था, न कि रेफरी को, जो रेफरी द्वारा निर्णय दिया गया वो एक पुरस्कार है और आपत्ति याचिका में दिए गए कारणों से यह पुरस्कार रद्द किया जा सकता है। यह कहा गया कि गंगा राम, लख्मी चंद, टेक चंद, माम चंद और रणजीत मध्यस्थों की सोम दत्त के साथ मिलीभगत थी और उन्होंने उसकी बात सुने बिना ही फैसला दे दिया। उन्होंने उसे कोई नोटिस नहीं दिया और न ही उसे कोई सबूत पेश

करने के लिए कहा गया। सोम दत्त वादी ने अपने जवाब में इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि सूरज कौर प्रतिवादी को रेफरी के फैसले के खिलाफ आपत्तियां भरने से रोक दिया गया था। इन आपत्तियों से उत्पन्न होने वाले आवश्यक मुद्दों को 27 अप्रैल, 1973 को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किया गया था, और मामले को प्रतिवादी-आपत्तिकर्ता श्रीमती सूरज कौर के साक्ष्य के लिए 28 अगस्त, 1973 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

6) हालाँकि, उस तारीख से पहले सूरज कौर ने 6 अगस्त, 1973 को वरिष्ठ उप-न्यायाधीश की अदालत में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुकदमे में शामिल बिंदु दो वसीयतों के तथ्य और वैधता से संबंधित थे और रेफरी का संदर्भ था। इन मामलों के संबंध में निर्णय देना अवैध था और रेफरी कोई बयान देने या कोई निर्णय देने में सक्षम नहीं थे और इसलिए, रेफरी के संदर्भ और उनके निर्णय को अवैध होने के कारण खारिज किया जा सकता है और मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जा सकता है। वादी ने इस याचिका को तुच्छ बताते हुए इसका विरोध किया। आरोप था कि ऐसा मामले की सुनवाई को लंबा खींचने के मकसद से किया गया था। पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद वरिष्ठ उप-न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी वसीयत या वसीयत की वास्तविकता या अन्यथा का प्रश्न मध्यस्थों या रेफरी के पास नहीं भेजा जा सकता है और इसका निर्णय कानून के अनुसार किया जाना चाहिए और वह रेफरी का संदर्भ अमान्य था और इसलिए, उन्होंने 28 नवंबर, 1973 के अपने आदेश से रेफरी के संदर्भ और उनके निर्णय को अमान्य कर दिया। व्यथित महसूस करते हुए, सोम दत्त वादी ने इस आदेश के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील दायर की। न्यायाधीश, गुड़गांव, जिसकी सुनवाई अंततः गुड़गांव में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला द्वारा की गई। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 9 अक्टूबर, 1974 को अपने फैसले में कहा कि मामले के निर्णय के लिए रेफरी का संदर्भ वैध था और रेफरी का निर्णय साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के अर्थ में एक बयान था और यह था इसे स्वीकारोक्ति के रूप में पार्टियों पर बाध्यकारी कर दिया गया और प्रतिवादी को कोई भी आपत्ति दर्ज करने से रोक दिया गया। परिणामस्वरूप उन्होंने वरिष्ठ उप-न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए उसके पास भेज दिया। इसके बाद सुरजीत कौर प्रतिवादी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के इस आदेश के खिलाफ वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।

7) याचिकाकर्ता के वकील श्री जी.सी.मित्तल का पहला तर्क यह है कि वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, गुड़गांव का 28 नवंबर, 1973 का आदेश, जिसके तहत उन्होंने प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार किया था, अपील योग्य नहीं था और, इसलिए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव का 9 अक्टूबर, 1974 का आक्षेपित निर्णय क्षेत्राधिकार के बिना है और इस संक्षिप्त आधार पर रद्द किया जा सकता है। यह आपत्ति याचिकाकर्ता सूरज कौर की ओर से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष भी उठाई गई थी, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया था। इस आपत्ति से निपटने में उन्होंने 9 अक्टूबर, 1974 के अपने फैसले के पैरा संख्या 6 में निम्नानुसार कहा: -

> "जहां एक रेफरी को संदर्भ दिया गया है, समझौते के अनुसरण में रेफरी द्वारा दिया गया बयान पार्टियों पर बाध्यकारी है। ऐसे समझौते के बाध्यकारी चरित्र का वास्तविक आधार यह है कि मूल अनुबंध के बयान का पालन करना है जैसे ही रेफरी बयान देता है, तीसरे व्यक्ति को बयान के संदर्भ में दावे के समायोजन में निपुण किया जाता है। एक पक्ष द्वारा

एक प्रस्ताव है और दूसरे द्वारा स्वीकृति है जिसके लिए विचार पारस्परिकता है। इस प्रकार, का बयान रेफरी आदेश 23, नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान किए गए पक्षों के दावे के समायोजन के बराबर है, और एक अपील अदालत के एक आदेश से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43, नियम एल (एम) के तहत की जाती है। बयान दर्ज करने से इंकार कर दिया गया। इसलिए, अपील की विचारणीयता के संबंध में प्रतिवादी की पहली आपत्ति को पूर्वगामी कारणों से खारिज कर दिया गया है। यदि इस बिंदु पर किसी अधिकार की आवश्यकता है, तो हम सीधे अपने स्वयं के उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं राम नारायण और अन्य बनाम संतोष कुमार और अन्य (1)।"

राम नारायण के मामले में (सुप्रा) जिस पर निचली अपीलीय अदालत ने भरोसा किया था, इसमे निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:-

"जहां साझेदारी और खातों के विभाजन और विघटन के मुकदमे में पार्टियों ने मामले को रेफरी के पास भेजा और रेफरी ने अदालत को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि पार्टियों ने मामले में समझौता कर लिया है। मैं यहां सभी पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित समझौता संलग्न कर रहा हूं और इसे मामले में मेरा बयान माना जाना चाहिए":

अभिनिर्धारित किया गया कि (1) ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया मध्यस्थता के संदर्भ में नहीं बल्कि एक रेफरी के संदर्भ में थी, (2) कि रेफरी द्वारा भेजा गया पत्र एक बयान के समान था, (3) कि इस पर विचार किया गया था अनुबंध जो पार्टियों के बीच दर्ज किया गया था और जो पारस्परिकता था, और (4) यह पार्टियों के दावों के समायोजन के बराबर था।

रेफरी का एक बयान आदेश XXIII, नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पार्टियों के दावों के समायोजन के बराबर है, और अपील कोर्ट रिकॉर्डिंग के एक आदेश से आदेश XLIII नियम एल (एम), सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत होती है।

यह निर्णय अलग है और इसका इस मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मौजूदा मामले में ट्रायल कोर्ट ने 28 नवंबर, 1973 के अपने आदेश में रेफरी के फैसले को दर्ज करने से इनकार नहीं किया, लेकिन बस यह माना कि इस मामले को रेफरी के पास निर्णय के लिए नहीं भेजा जा सकता है और यह संदर्भ अमान्य है और परिणामस्वरूप रेफरी का निर्णय अवैध एवं शून्य है। माना जाता है कि ट्रायल कोर्ट ने अभी तक रेफरी के बयान/निर्णय से संबंधित कोई निर्णय नहीं दिया है और यह अभी भी लंबित है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट ने पक्षों के बीच हुए समझौते को रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया और परिणामस्वरूप, आदेश 43, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 1 का खंड (एम) लागू नहीं हुआ और, इसलिए, आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई। वरिष्ठ उप-न्यायाधीश सक्षम थे। धारा 104(1), सिविल प्रक्रिया संहिता, बताती है कि एक अपील निम्नलिखित आदेशों से की जाएगी और इस संहिता के मुख्य भाग में या उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान की जाएगी, और किसी अन्य आदेश से नहीं: —

(एफएफ) धारा 35ए के तहत एक आदेश;
(जी) धारा 95 के तहत एक आदेश;

(ज) इस संहिता के किसी भी प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति की सिविल जेल में गिरफ्तारी या हिरासत में रखने का निर्देश देने का जुर्माना लगाने वाला आदेश, सिवाय इसके कि जहां ऐसी गिरफ्तारी या हिरासत किसी डिक्री के निष्पादन में हो;
(i) नियमों के तहत किया गया कोई भी आदेश जिसके खिलाफ अपील को नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दी जाती है।

इसलिए, मेरा मानना है कि वरिष्ठ उप-न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कोई अपील संभव नहीं थी और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का निर्णय क्षेत्राधिकार के बिना है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। यदि वादी वरिष्ठ उप-न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध व्यथित महसूस करता है तो उसे इस न्यायालय में इसके विरुद्ध पुनरीक्षण दायर करना चाहिए था। मैं यह भी देख सकता हूं कि राम नारायण के मामले (सुप्रा) में एकल पीठ के फैसले को साधु राम और अन्य बनाम उदे राम (2) के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिस पर नीचे चर्चा की जाएगी।

8) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह है कि रेफरी का संदर्भ अवैध था और इसे वसीयत या वसीयत की वैधता और वास्तविकता से संबंधित नहीं किया जा सकता है, कि रेफरी का निर्णय साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के अर्थ के अंतर्गत रेफरी का बयान नहीं है अपितु मामले का निर्णय है जोकि अमान्य है। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में यह मामला गंगा राम और अन्य की मध्यस्थता के लिए निर्णय के लिए भेजा गया था और यह बयान देने के लिए रेफरी के संदर्भ का मामला नहीं था। इस विवाद के समर्थन में उन्होंने विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया।

9) श्रीमती खेलावती बनाम चेत राम और अन्य (3) में, इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -
"वसीयत की वास्तविकता या अन्यथा का प्रश्न मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वसीयत की प्रोबेट से निपटने वाले कानून के अनुसार तय किया जाना चाहिए।"

मोनमोहिनी गुहा बनाम बंगा चंद्र दास (4) में भी इसी प्रकार का कानून अभिनिर्धारित किया गया था।

10) साधु राम के मामले (सुप्रा) में, तथ्य यह थे कि 30 जून, 1962 को, एक उदे राम ने यह घोषणा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया था कि मुकदमे के पक्षकारों वाले संयुक्त हिंदू परिवार में विघ्न आ गया था और उन्होंने विभाजन के माध्यम से आधे हिस्से का दावा किया था। वादपत्र से संलग्न अनुसूची में सूचीबद्ध संयुक्त संपत्तियां और संपत्तियों से आय के संबंध में खातों का प्रतिपादन, या इसके विकल्प में
कुछ कथित साझेदारियों का विघटन की माँग की गई । सुनवाई की पहली तारीख पर प्रतिवादियों ने साझेदारी विलेख में निहित मध्यस्थता समझौते के आधार पर मुकदमे की कार्यवाही को रोकने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन दिया, जिसके तहत फर्म अस्तित्व में आई थी। कोर्ट ने 7 सितंबर 1962 को आदेश पारित किया और मुकदमे के उस हिस्से की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई जिसमें साझेदारी के विघटन और खातों के प्रतिपादन का उल्लेख था। वादी को मुकदमे को विभाजित करने और यदि वह चाहे तो मुकदमा आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी, जहां तक यह संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के विभाजन से संबंधित था। वादी ने मुकदमे के दूसरे भाग पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ दायर की जाने वाली अपील के

परिणाम के अधीन ऐसा करने के लिए चुना। उस आदेश के विरुद्ध एक अपील वास्तव में दायर की गई थी और इस न्यायालय द्वारा उसे तुरंत खारिज कर दिया गया था। इसलिए वादी ने संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा आगे बढ़ाया। इस बीच वादी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे कथित साझेदारी से संबंधित मामलों के संबंध में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक अलग मामले के रूप में पंजीकृत किया गया था। परंतु मध्यस्थ के चुनाव के मामले में पार्टियां सहमत होने में विफल रही थी। मध्यस्थता अधिनियम के तहत मुकदमा और कार्यवाही दोनों 19 अगस्त, 1963 को सुनवाई के लिए आए। उस तारीख को पार्टियों और उनके वकील द्वारा निम्नानुसार बयान दिया गया था: -

> "एल लक्ष्मी चंद को पार्टियों के बीच विवादों के लिए एकमात्र रेफरी के रूप में नियुक्त किया जाए। वह जिस भी निर्णय पर पहुंचेंगे वह हमें पूरी तरह या पूरी तरह से स्वीकार्य होगा। वह पक्षों को सुन सकता है, साक्ष्य दर्ज कर सकता है या ऐसा नहीं भी कर सकता है। प्रतिवादी इस तथ्य को जानते हैं कि एल लक्ष्मी चंद वादी के वकील हैं।

एल. लक्ष्मी चंद उस समय कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने रेफरी के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी। एल. लक्ष्मी चंद रेफरी ने 28 अक्टूबर, 1963 को अदालत में अपना लिखित बयान दायर किया जिसमें उन्होंने पक्षों के बीच मुकदमेबाजी का इतिहास बताया और उन दोनों के बीच विवाद के सभी बिंदुओं पर अपना निर्णय दिया जो अभी भी लंबित थे। संयुक्त संपत्ति के विभाजन के मुकदमे में न्यायालय के समक्ष, साथ ही वे मामले जिनके संबंध में मुकदमा रुका हुआ था और जो दीवान शाम लाई, अधिवक्ता की मध्यस्थता के संदर्भ का विषय-वस्तु थे। रेफरी ने पार्टियों के शेयरों के बारे में निर्णय दिया और संपत्ति को उनके बीच मेट्स और बाउंड द्वारा विभाजित किया और यह भी कहा कि एक निश्चित आकस्मिकता में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को 60,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाना था। रेफरी ने पार्टियों से दावों और प्रतिदावों के लिखित बयान लेने और उनके साक्ष्य दर्ज करने के बाद निर्णय दिया था और इन सभी कार्यवाही को अदालत के सामने रखा था। इन तथ्यों पर इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा यह माना गया कि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के अर्थ के तहत एक रेफरी को दिया गया संदर्भ नहीं था और यह एक मध्यस्थ का संदर्भ था और उसके द्वारा दिया गया निर्णय एक है पुरस्कार और साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के तहत एक बयान नहीं।

11) मैसर्स में. राम लाई जगन नाथ बनाम पंजाब राज्य (5), तथ्य यह थे कि मुद्रित कार्य अनुबंध प्रपत्र में इस आशय का एक खंड था कि विवाद के मामले में मामला कुछ प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसका आदेश अंतिम होगा। उस मामले में निर्णय के लिए जो मुद्दा सामने आया वह यह था कि क्या यह खंड वैध मध्यस्थता समझौते के बराबर है या नहीं। इन तथ्यों पर इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया: -

> "मध्यस्थता अधिनियम में जो निर्धारित है उससे अलग मध्यस्थता करने के लिए एक समझौते को किसी विशेष प्रकार के शब्दों में बताने की आवश्यकता नहीं है और 'मध्यस्थता' और 'मध्यस्थ' जैसे तकनीकी या औपचारिक शब्दों के उपयोग की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि पार्टियों को मध्यस्थता के लिए एक संदर्भ या प्रस्तुत करने का इरादा रखना चाहिए और इस संबंध में इरादा शुरुआत से ही होना चाहिये होना चाहिए। इस खंड को इसके संदर्भ में तर्कसंगत रूप से विचार करने पर, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पार्टियों का इरादा निर्दिष्ट प्राधिकारी को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का था। इसके अलावा 'संदर्भ' को धारा 2(ई) (मध्यस्थता अधिनियम) में 'मध्यस्थता के संदर्भ' के रूप में परिभाषित

किया गया है। संदर्भ और उपस्थित परिस्थितियों में 'मध्यस्थ' या 'मध्यस्थता' जैसे शब्दों की अनुपस्थिति पूरी तरह से सारहीन है क्योंकि उनकी चूक भाषा द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है कि मामला, विवाद के मामले में, निर्दिष्ट को संदर्भित किया जाएगा। प्राधिकारी जिसका आदेश अंतिम होगा।"

12) इन सभी निर्णयों में निर्धारित कानून इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होता है। मौजूदा मामले में, वादी सोम दत्त द्वारा स्थापित वसीयत और प्रतिवादी सूरज कौर द्वारा स्थापित अपंजीकृत वसीयत की वैधता और तथ्य विवाद में थे। इसलिए, खेला वती के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून के मद्देनजर, इन बिंदुओं को किसी मध्यस्थ के निर्णय के लिए या साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के तहत एक बयान के लिए रेफरी को नहीं भेजा जा सकता है। वर्तमान मामले में पार्टियों द्वारा किए गए संयुक्त आवेदन के अनुसार, गंगा राम सरपंच और छह अन्य को मुकदमे में शामिल पक्षों के बीच विवाद के सभी बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया था और वे उपस्थित या अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज कर सकते थे। पक्ष और कोई अन्य पूछताछ कर सकते थे और उनका निर्णय अंतिम माना जाता था। इसलिए, यह रेफरी के संदर्भ का मामला नहीं था बल्कि मामले में विवाद के सभी बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता का संदर्भ था।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 इस प्रकार है: -

"उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान, जिन्हें मुकदमे के एक पक्ष ने विवादग्रस्त मामले के संदर्भ में जानकारी के लिए स्पष्ट रूप से संदर्भित किया है, स्वीकारोक्ति हैं।"

इस खंड के अंतर्गत दिया गया चित्रण इस प्रकार है: -

“सवाल यह है कि क्या ए द्वारा बी को बेचा गया घोड़ा स्वस्थ है।

A, B से कहता है "जाओ और C से पूछो, C को इसके बारे में सब पता है"। सी का कथन एक स्वीकारोक्ति है।"

छब्बा लाई बनाम कल्लू लाई और अन्य (6) में, इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -

"मुकदमे में विवाद के मामलों पर निर्णय लेने के लिए किसी बाहरी पक्ष का संदर्भ और लागत का प्रश्न विवाद के मामले के संदर्भ में जानकारी के लिए उस पक्ष का संदर्भ नहीं है, और यदि संदर्भ को केवल धारा के तहत माना जाता है 20, यह एक अमान्य सन्दर्भ है।”

साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, यदि किसी मुकदमे का कोई पक्ष किसी तीसरे पक्ष द्वारा दिए गए तथ्य के बयान से बाध्य होने के लिए सहमत होता है, तो उस तीसरे पक्ष का बयान, जब दिया जाता है, उस पक्ष द्वारा स्वीकारोक्ति के रूप में माना जाता है जो प्रस्ताव दिया है, और यदि दोनों पक्ष किसी मामले को तीसरे पक्ष को सौंपने के लिए सहमत हैं तो उसका बयान दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस खंड में 'सूचना' शब्द का अर्थ तथ्य के प्रश्न पर एक बयान है, न कि किसी प्रकार का निर्णय। साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के तहत किसी तीसरे पक्ष के संदर्भ के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि संदर्भ रेफरी की जानकारी में तथ्य के प्रश्न पर हो। अब, मौजूदा मामले में, मामले को निर्णय के लिए गंगा बाम और छह अन्य, तथाकथित रेफरी के पास भेजा गया था। इस मामले में पार्टियों द्वारा स्थापित दो वसीयतों की

तथ्यात्मकता, वास्तविकता और वैधता से संबंधित प्रश्न शामिल थे और इन बिंदुओं पर इन रेफरी के निर्णय को तथ्य के प्रश्न पर एक बयान नहीं कहा जा सकता है। ये रेफरी पार्टियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करने के हकदार थे या वे कोई साक्ष्य दर्ज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं या कोई अन्य पूछताछ कर सकते हैं और उनका निर्णय अंतिम होना था। यह इन व्यक्तियों को तथ्य के प्रश्न पर बयान देने के लिए एक संदर्भ नहीं था, बल्कि मामले का निर्णय उन्हें संदर्भित किया गया था और यह मामले को तय करने के लिए मध्यस्थता के लिए एक संदर्भ था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का यह निर्णय कि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के तहत एक रेफरी को दिया गया संदर्भ था, गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

13) ऊपर दिए गए कारणों से, यह माना जाता है कि गंगा राम और अन्य को जो संदर्भ दिया गया था वह मध्यस्थता के लिए था, न कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के तहत बयान देने के लिए और वसीयत की वास्तविकता या वैधता से संबंधित कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। एक मध्यस्थ को संदर्भित किया गया था और इसलिए, यह संदर्भ पूरी तरह से अवैध था।

वादी-प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री एस.पी. जैन ने माउंट अकबरी बेगम बनाम रबमत हुसैन और अन्य (7) पर भरोसा किया, इसे इस प्रकार माना गया: -

"किसी विशेष गवाह के बयान का पालन करने का समझौता वास्तव में मध्यस्थता का संदर्भ नहीं है। मध्यस्थता का सार यह है कि मध्यस्थ मामले का निर्णय करता है और उसका पुरस्कार एक निर्णय की प्रकृति का होता है जिसे बाद में न्यायालय की डिक्री में शामिल किया जाता है। मध्यस्थ या तो अपने ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ सकता है या पूछताछ कर सकता है और सबूत ले सकता है और फिर ऐसे सबूतों पर अपना निर्णय दे सकता है। लेकिन जहां पार्टियां किसी तीसरे व्यक्ति या रेफरी के बयान का पालन करने के लिए सहमत होती हैं, रेफरी केवल अपने ज्ञान या विश्वास के अनुसार एक बयान देता है और फिर अदालत मामले का फैसला करती है और ऐसे बयान के आधार पर अपना फैसला सुनाती है और एक फैसला सुनाती है। उस पर डिक्री. रेफरी पूछताछ करने और साक्ष्य लेने और फिर ऐसे साक्ष्य के आधार पर अपने निर्णय की घोषणा करने के लिए अधिकृत नहीं है। उसे अपने ज्ञान या विश्वास के अनुसार बयान देने के लिए कहा जाता है। मध्यस्थता के मामले में, चूंकि मध्यस्थ का निर्णय एक राय की अभिव्यक्ति है और उसकी प्रक्रिया एक न्यायालय के समान होती है, एक पक्ष आपत्ति दर्ज करने और पुरस्कार की वैधता को चुनौती देने का हकदार है। रेफरी या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा बयान देने का उसके द्वारा की गई कार्यवाही से कोई समानता नहीं है जैसे कि वह कानून का न्यायालय हो और तदनुसार इसकी वैधता के बारे में आपत्तियां दर्ज करने की कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती है। निर्णय सुनाते समय इसके प्रभाव पर विचार करना न्यायालय का काम है। धारा 20 के तहत किसी तीसरे पक्ष के संदर्भ के प्रयोजनों के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि संदर्भ रेफरी के ज्ञान के भीतर तथ्य के प्रश्नों पर होना चाहिए।

उसी प्रभाव के लिए उमराली अली खान और में निर्धारित कानून था
अन्य बनाम इंतिजामी बेगम और अन्य (8), नारायण दास और अन्य बनाम फर्म घासी राम गोजर माई (9) और अब्दुल रहमान बनाम कल्लू खान (10)। पहले दो निर्णयों में, माउंट अफकबरी बेगम के मामले (सुप्रा) में उपर्युक्त पूर्ण पीठ के फैसले का पालन किया गया था। ये निर्णय प्रतिवादी के वकील के तर्क का समर्थन नहीं करते, बल्कि याचिकाकर्ता का समर्थन करते हैं। इन निर्णयों के अनुसार जिस रेफरी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के तहत जानकारी के लिए संदर्भ दिया गया है, वह पूछताछ करने और साक्ष्य लेने और फिर ऐसे साक्ष्य

के आधार पर अपने निर्णय की घोषणा करने के लिए अधिकृत नहीं है और उसे बस एक निर्णय लेने के लिए कहा जाता है। उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार बयान दिया जाता है और अदालत मामले का फैसला करती है और ऐसे बयान के आधार पर फैसला सुनाती है। दूसरी ओर मध्यस्थ मामले का निर्णय करता है और उसका पुरस्कार निर्णय की प्रकृति का होता है जिसे बाद में डिक्री में शामिल किया जाता है और मध्यस्थ या तो अपने ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ सकता है या पूछताछ कर सकता है और साक्ष्य ले सकता है और फिर निर्णय ले सकता है।

14) उपर्युक्त निर्णयों के विश्लेषण से, कानूनी स्थिति जो उभरती है वह यह है कि वसीयत की वैधता या वास्तविकता या अन्यथा का प्रश्न साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मध्यस्थता या रेफरी के पास नहीं भेजा जा सकता है और इसका निर्णय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वसीयत की प्रोबेट से संबंधित कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। । किसी मुकदमे में विवादित मामलों पर निर्णय लेने के लिए किसी तीसरे पक्ष का संदर्भ और लागत का प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के अर्थ के अंतर्गत विवादग्रस्त मामले के संदर्भ में जानकारी के लिए उस पक्ष का संदर्भ नहीं है, बल्कि एक संदर्भ है मध्यस्थता के लिए है। उस अधिनियम की धारा 20 में 'सूचना' शब्द का अर्थ तथ्य के प्रश्न पर एक बयान है, न कि किसी प्रकार का निर्णय। यदि पार्टियां किसी रेफरी के बयान का पालन करने के लिए सहमत होती हैं तो रेफरी केवल तथ्य के प्रश्न पर अपने ज्ञान या विश्वास के अनुसार एक बयान देता है और यह बयान उस पार्टी या पार्टियों की स्वीकृति माना जाता है, जिन्होंने संदर्भ दिया है साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 और न्यायालय मामले का फैसला करता है और ऐसे बयान के आधार पर निर्णय सुनाता है और उस पर डिक्री पारित करता है। एक रेफरी पूछताछ करने और साक्ष्य लेने और फिर ऐसे साक्ष्य के आधार पर निर्णय सुनाने का हकदार नहीं है।

15) हालाँकि, मध्यस्थता का सार यह है कि मध्यस्थ मामले का फैसला करता है और पक्ष आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं और उसके फैसले की वैधता को चुनौती दे सकते हैं, और अगर फैसला बरकरार रखा जाता है, तो यह एक फैसले की प्रकृति में होता है जिसे बाद में कोर्ट की एक डिक्री में शामिल किया जाता है। मध्यस्थ या तो अपने ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ सकता है या पूछताछ कर सकता है और साक्ष्य रिकॉर्ड कर सकता है और फिर ऐसे साक्ष्य पर अपना निर्णय दे सकता है।

16) ऊपर दिए गए कारणों से, यह पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव के 9 अक्टूबर, 1974 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, गुड़गांव के 28 नवंबर, 1973 के आदेश को बहाल कर दिया जाता है। पक्षों को उनके वकील के माध्यम से 14 नवंबर, 1975 को वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, गुड़गांव की अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है, जो फिर मुकदमे की सुनवाई और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसमें शामिल कानून के बिंदु को देखते हुए, हर्ज़े के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी

भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वीरेंद्र कुमार
प्रीक्षिशु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़